भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3761
जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
27अग्रहायण, 1946 (शक)

महाराष्ट्र में डिजिटल इंडिया पहल

3761.डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय डिजिटल इंडिया पहल का समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में स्थानीय सरकारों और एजेंसियों के साथ किस प्रकार सहयोग करता है; और
(ख) ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन और अवसंरचना विकास के संबंध में चिंताओं अथवा विवादों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क):इलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय (एमईआईटीवाई) नेडिजिटलइंडियापहलकेसमयपरऔरप्रभावीकार्यान्वयनकोसुनिश्चितकरनेकेलिएमहाराष्ट्रराज्यसहितपूरेभारतमेंस्थानीयसरकारोंऔरएजेंसियोंकेसाथसहयोगकरनेमेंमहत्वपूर्णभूमिकानिभाईहै।
इसकार्यक्रममेंशामिलविभिन्नएजेंसियोंकेबीचसमन्वयसुनिश्चितकरनेकेलिएसरकारद्वारानिम्नलिखितकदमउठाएगएहैं।

- राज्योंऔरसंघशासितप्रदेशों, विशेषकरराज्यसूचनाप्रौद्योगिकी (आईटी) विभागोंकेसाथनियमितबैठकेंऔरसम्मेलन/कार्यशालाएं।
- तालमेलऔरसहयोगबनानेकेलिएअंतर-मंत्रालयीबैठकें।
- विभागोंकीउद्योगोंकेसाथनियमितबैठकेंऔरकार्यशालाएं।
- डिजिटलइंडियाकेअंतर्गतविभिन्नपहलोंकीगहननिगरानी।

इसकेअलावा, एमईआईटीवाईभारतकेविभिन्न टियर-2और टियर-3 शहरोंमेंप्रौद्योगिकीऔरउद्यमिताकेविकासकेलिएराज्यसरकारोंकेसाथसक्रियरूपसेकामकरताहैजिसकानेतृत्वसॉफ्टवेयरटेक्नोलॉजीपार्कऑफइंडिया (एसटीपीआई) औरनेशनलइंस्टीट्यूटऑफइलेक्ट्रॉनिक्सएंडइंफॉर्मेशनटेक्नोलॉजी (नाईलिट) जैसेसंगठनोंद्वाराकियाजाताहै। इसकेअलावा, इलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय (एमईआईटीवाई) काएकसंलग्नकार्यालय,

राष्ट्रीयसूचनाविज्ञानकेंद्र (एनआईसी) केपूरेभारतमेंराज्यस्तरऔरजिलास्तरपरअपनेराज्यकेंद्रहैं। येराज्यऔरजिलाकेंद्रविभिन्नआईसीटीअनुप्रयोगोंकोविकसित

करनेऔरलागूकरनेमेंविभिन्नराज्यऔरजिलास्तरकेसरकारीकार्यालयोंकोनिरंतरमार्गदर्शनऔरसहायताप्रदान करतेहैं।

(ख):सरकारनेडिजिटलडिवाइडकोपाटनेकेलिएकईकदमउठाएहैं,
जिनमेंनागरिकोंकोसार्थककनेक्टिविटीप्रदानकरनेसेलेकरआवश्यकडिजिटलबुनियादीढांचाऔरनागरिकोंको डिजिटलसाक्षरताप्रदानकरनाशामिलहै। 94 करोड़सेअधिकनागरिकइंटरनेटकेमाध्यमसेजुड़ेहुएहैं। सरकारद्वाराकीगईकुछप्रमुखपहलेंइसप्रकारहैं:

(i) डिजिटलसाक्षरतादरमेंसुधारकरनेकेलिए, विशेषरूपसेग्रामीणभारतमें, भारतसरकारनेमहाराष्ट्रसहितदेशभरमें 6 करोड़ग्रामीणपरिवारों (प्रतिपरिवारएकव्यक्ति) कोकवरकरकेग्रामीणभारतमेंडिजिटलसाक्षरतालानेकेलिए "प्रधानमंत्रीग्रामीणडिजिटलसाक्षरताअभियान (पीएमजीदिशा)" नामकएकयोजनालागूकी। 31 मार्च 2024 तक 6 करोड़केमुकाबलेपूरेदेशमें 6.39 करोड़व्यक्तियोंकोप्रशिक्षितकियागया।

(ii) कॉमनसर्विससेंटर (सीएससी) ग्रामीणक्षेत्रोंमेंग्रामस्तरीयउद्यमियों (वीएलई) केमाध्यमसेडिजिटलमोडमेंसरकारीऔरव्यावसायिकसेवाएंप्रदानकररहेहैं। सीएससीकेमाध्यमसे 800 सेअधिकसेवाएंप्रदानकीजारहीहैं, जिनमेंसरकारीसेवाएं, वित्तीयसेवाएंऔरआधारसेसंबंधितसेवाएं, विभिन्नसामाजिककल्याणयोजनाएं, शिक्षा, टेली-मेडिसिन, यात्राबुकिंग, उपयोगिताभुगतानशामिलहैं। अक्टूबर, 2024 तक, देशभरमें (ग्रामीण + शहरी) 5.84 लाखसीएससीकार्यरतहैं, जिनमेंसे 4.63 लाखसीएससीग्रामपंचायत (ग्रामीण) स्तरपरकार्यरतहैं।

(iii) दुनियाकीसबसेबड़ीग्रामीणदूरसंचारपरियोजनाओंमेंसेएकभारतनेटपरियोजनाकोदूरसंचारविभागद्वाराच रणबद्धतरीकेसेक्रियान्वितकियाजारहाहै, ताकिसभीग्रामपंचायतों (जीपी) औरगांवोंकोब्रॉडबैंडसेजोड़नेकेलिएनेटवर्कबनायाजासके। अक्टूबर 2024 तकदेशमेंभारतनेटपरियोजनाकेतहत 2,14,283 जीपीकोसेवाकेलिएतैयारकरदियागयाहै।

(iv) इसकेअलावा, देशभरकेनागरिकोंकोविभिन्नपहलोंकेतहत ई-सेवाओंतकपहुंचबनानेमेंसक्षमबनायागयाहै, जैसेकिन्यू-एजगवर्नेंसकेलिएएकीकृतमोबाइलएप्लिकेशन (उमंग), माईस्कीम ,डिजीलॉकर , ई-हॉस्पिटलऔरमाईगोवआदि।

****